जितना कठिन संघर्ष होगा उतना मीठा फल होगा।
– अज्ञात

नौसेना अभ्यास का विशेष कूटनीतिक अहमियत

भारत ने जापान और अमेरिका के साथ ही इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित करने का फैसला किया है। औपचारिक आमंत्रण भेजने की प्रक्रिया अगले हफ्ते पूरी होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने संकेत दे दिया है कि इस कवायद का हिस्सा बनने में उसकी पूरी दिलचस्पी है।

मोहन वर्मा।

साल 1992 में शुरू हुआ और 2004 से हर साल होने वाला मलाबार नौसेना अभ्यास इस बार विशेष कूटनीतिक अहमियत हासिल करने जा रहा है। भारत ने जापान और अमेरिका के साथ ही इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित करने का फैसला किया है। औपचारिक आमंत्रण भेजने की प्रक्रिया अगले हफ्ते पूरी होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने संकेत दे दिया है कि इस कवायद का हिस्सा बनने में उसकी पूरी दिलचस्पी है।

मतलब यह कि अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो साल के आखिर में होने वाले इस नौसेना अभ्यास में पहली बार अनौपचारिक समूह क्वाड के चारों सदस्य देश– भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मलाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होंगे।

भारत और चीन के बीच गलवान सीमा पर हुए हालिया टकराव की पृष्ठभूमि में बंगाल की खाड़ी में होने वाले इस नौसेना अभ्यास का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ध्यान रहे, साउथ चाइना सी में चीन के दावों ने दुनिया के तमाम बड़े देशों को असहज कर रखा है। वह इस समुद्री क्षेत्र के 90 फीसदी हिस्से पर अपना अधिकार जता रहा है जबकि उस रास्ते पूरी दुनिया के मालवाही पोत गुजरते हैं और सालाना करीब 3 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है। आश्चर्य नहीं कि इसी महीने जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस विवादित हिस्से में नेवी ड्रिल को अंजाम दिया तो उसके बीच में ही अमेरिका ने वहां दो परमाणु हथियार संपन्न विमान वाहक पोत– यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन भेज दिए। साफ है कि इस इलाके में चीन की बढ़ती दावेदारी को नियंत्रित करना सभी को जरूरी लग रहा है। इस संदर्भ में बंगाल की खाड़ी में आयोजित चार बड़े लोकतांत्रिक देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास चीन पर अंकुश लगाने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। गौरतलब है कि एक अनौपचारिक क्षेत्रीय समूह के रूप में क्वाड 2004 में अस्तित्व में आया, जिसका मकसद हिंद महासागर के तटवर्ती देशों को सूनामी से आए विनाश से उबरने में मदद पहुंचाना था। 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया लेकिन यह पहला मौका है जब इस ग्रुप के चारों सदस्य देश एक साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, भले ही बैनर क्वाड का नहीं बल्कि मलाबार नौसेना अभ्यास का है।

चीन इन देशों के साथ आने को लेकर पहले से ही काफी संवेदनशील रहा है। इससे पहले 2007 में भी चीन ने एतराज जताया था, जब मलाबार सैन्य अभ्यास के तहत ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका, जापान, सिंगापुर और भारत के साथ शिरकत की थी तो 2015 में जब भारत और अमेरिका के साथ जापान इस अभ्यास में शामिल हो रहा था तब भी चीन ने आपत्ति की थी। लेकिन यह एक प्रतिरक्षात्मक कवायद है जिसका मकसद किसी को भयभीत करना नहीं है। यह सबके हित में होगा कि साउथ चाइना सी समेत इस पूरे इलाके में शांति–सौहार्द का माहौल बना रहे।

मनोवैज्ञानिक पहलू

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

एक समस्या आपको अलग–अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। पहले स्तर पर उसे कई व्यवहारिक चुनौतियों से निपटना होगा जैसे कि पढ़ना, लोगों को देखना, टी वी देखना। और दूसरे स्तर पर उसे इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जूझना होगा। व्यवहारिक हिस्सा किसी भी व्यक्ति के ऊर्जा का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा को खत्म करेगा जबकि मनोवैज्ञानिक पहलू बाकी बचा 75 प्रतिशत हिस्सा निगल जाता है। परिणामस्वरूप वह अधिकतर समय अपने माता–पिता और अपने भविष्य के बारे में सोचने में गुजारेगा। अगर कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार लेता है कि वो अंधा होने वाला है तो उन मनोवैज्ञानिक नकारात्मकताओं का कोई अस्तित्व नहीं रह जायेगा जो बाकि के 75 प्रतिशत ऊर्जाओं को नष्ट कर देते हैं।

संपादकीय

पहुंच बढ़ाने पर हो जोर

आज भले ही ऐसा लग रहा है कि लाखों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीख गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश की आधी आबादी के लिए अभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल एक नई चीज है। इसलिए यदि सरकार और ट्राई का अंकुश कमजोर पड़ता है और प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों को मनमाने ढंग से पांव पसारने की छूट दी जाती है, तो यह अंततरू इंटरनेट के प्रसार के खिलाफ जाएगा। ज्यादा जरूरी यह है कि इंटरनेट को समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। ऐसे एक गड़बड़झाले का खुलासा 2016 में हुआ था।

सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर विनोद रंगनाथन नाम के शख्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में एक ऐसी ही जानकारी निकलवाई थी। इसमें पता चला था कि देश का राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय को 34 एमबीपीएस की गति वाला इंटरनेट कनेक्शन मुहैया करा रहा था, जबकि उसी दौरान देश में औसत इंटरनेट कनेक्शन की गति मात्र 2 एमबीपीएस थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश की आम गरीब–मध्यवर्गीय जनता को बेहतर ताकत वाले सर्वर और अच्छी गति वाले इंटरनेट की जरूरत नहीं है? बेशक साधन–संपन्न लोगों के लिए प्रीमियम प्लान्स के एवज में ज्यादा पैसा देना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब तो सरकारी योजनाओं से लेकर स्कूली पढ़ाई तक यह सेवा गांव–देहात के उन लोगों के लिए भी जरूरी हो गई है जो इंटरनेट के लिए एक भी पैसा अतिरिक्त खर्च नहीं कर सकते। निश्चय ही यह काम मुफ्त में नहीं हो सकता, लेकिन इस क्रम में व्यापक आधार वाला वह कारोबारी मॉडल तो खड़ा किया ही जा सकता है जिसमें नेट न्यूट्रलिटी के नियम–कायदे खारिज न होते हों।

ट्राई ने कहा है कि इन प्लान्स की वजह से उन यूजर्स की सर्विस पर असर पड़ सकता है, जो प्रीमियम सेवाएं नहीं लेते हैं।

क्या करेगा ट्राई

संजय वर्मा।

बीते चार महीनों में ही न जाने कितने कामकाज 'वर्क फ्रॉम होम' पॉलिसी के रास्ते इंटरनेट के रहमो–करम पर आ गए हैं। ऐसे में यह जानकारी कुछ लोगों को खुश तो काफी लोगों को परेशान करेगी कि देश की कुछ टेलिकॉम कंपनियों ने ग्राहकों को दुहने के लिए हाई स्पीड डेटा और प्रायॉरिटी सर्विस वाले ज्यादा महंगे प्लान पेश किए हैं। अमीर ग्राहकों को ध्यान में रखकर ऊंची कीमतों पर पेश किए गए इन प्लांस के तहत बाकियों के मुकाबले बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया गया है। हालांकि दूरसंचार नियामक ट्राई ने फिलहाल नेट न्यूट्रलिटी का हवाला देते हुए इन प्लान्स पर रोक लगा दी है। ट्राई ने कहा है कि इन प्लान्स की वजह से उन यूजर्स की सर्विस पर असर पड़ सकता है, जो प्रीमियम सेवाएं नहीं लेते हैं।

इससे लगता है कि इंटरनेट की स्पीड को लेकर देश में कुछ बड़े झोल कायम हैं, जिन पर आम उपभोक्ताओं के हित में निगाह रखना और रोक लगाना जरूरी है। लेकिन जब टेलिकॉम सेक्टर का सारा खेल गिने–चुने बड़े खिलाड़ियों तक सिमट गया हो तो सवाल उठता है कि ट्राई आखिर कब तक ग्राहक हितों की रखवाली कर सकेगा। हालांकि ट्राई को यह अहसास हो गया

है कि ये कंपनियां अमीरों को बाकियों से बेहतर नेटवर्क और सर्विसेज देने का इंतजाम उसी डेटा हाई–वे पर एक अलग लेन बनाकर कर रही थीं, जो स्पेक्ट्रम के रूप में एक सार्वजनिक संसाधन का इस्तेमाल करता है। सरकारी नीलामी में मिले स्पेक्ट्रम का ज्यादा फायदा अमीरों को दिलाने का यह मामला कुछ–कुछ वैसा ही है, जैसे गरीबों की सेवा के लिए सस्ते में मिली जमीन पर बने स्कूल और अस्पताल सिर्फ अमीरों की सेवा में लग जाएं और गरीबों को दरवाजे से ही लौटा दें।

आम तौर पर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) ग्राहकों पर यह बंदिश नहीं लगाता कि वे लिए गए प्लान का इंटरनेट पर बातचीत करने में, विडियो देखने में या फिर ऑनलाइन खरीदारी करने में इस्तेमाल करें या फिर इन अलग–अलग कामों के लिए अलग–अलग शुल्क दरों पर भुगतान करें। किंतु यह एक जटिल बिजनेस मॉडल है जिसकी बारीकियां हमें चौंकाती हैं। इस बिजनेस मॉडल के तहत सर्विस प्रोवाइडरों की कोशिश यह रही है कि इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करने वाले उनके ग्राहक विभिन्न तरह के डेटा प्लान के लिए अलग–अलग शुल्क चुकाएं। एमबीपीएस वाले मॉडल में हालांकि ये कंपनियां ज्यादा तेज रफ्तार वाले इंटरनेट के लिए अलग से पैसा पहले से ही ले ही रही हैं। इसके बावजूद हमारे देश में ग्राहकों को इंटरनेट की वह स्पीड नहीं मिलती, जिसके वे हकदार हैं।

हाल यह है कि हमारे देश में 4जी वाले इंटरनेट उपभोक्ताओं को सिर्फ 11.46 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) की गति मिलती है, जो वैश्विक औसत 32.01 एमबीपीएस से काफी पीछे है। इस मामले में 140 देशों की सूची वाली ग्लोबल रैंकिंग में भारत 128वें स्थान पर आता है। दक्षिण कोरिया इसमें शीर्ष पर है जहां ग्राहक 103.18 एमबीपीएस की गति से इंटरनेट का आनंद लेते हैं।

अष्टयोग- 5115

3	5				1	
1	30	2	37	6	31	
	1	6			2	
6	37	3	34	1	25	5
	7		6		2	
	33	4	32	4	30	2
	3		4		6	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5114 का हल

6	1	7	4	3	5	2
2	28	4	40	7	35	4
1	2	5	6	4	7	3
5	28	3	38	6	34	1
4	2	6	3	5	1	7
3	31	2	24	1	30	6
7	6	1	4	2	3	5

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

विरोधाभास कुछ और भी है

मोहन। पड़ोसी मुल्क चीन के करीब 60 मोबाइल ऐप्स पर हाल में पाबंदी लगाई गई है। वहां भी 67.71 एमबीपीएस की स्पीड वाला इंटरनेट आम लोगों को हासिल है। विरोधाभास कुछ और भी हैं। जैसे मुमकिन है कि कुछ संगठनों से लेकर सरकारी संस्थाओं तक को ज्यादा तेज गति वाला कनेक्शन हासिल हो, जबकि आम नागरिक इंटरनेट की सुस्ती झेलने को त्रस्त हों। ऐसे में सवाल यह है कि जब ये कंपनियां इस पर अड़ जाएंगी कि उनके ग्राहक चुकाए गए पैसे के मुताबिक ही इंटरनेट की स्पीड हासिल कर पाएंगे, तब क्या किया जाएगा? इंटरनेट को इस तरह बांधना किसी भी इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वे फिल्टर लगाकर आसानी से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। यही वे बातें हैं जिनके चलते पिछले कुछ वर्षों में देश में नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा चर्चा में आया और संबंधित मामले ट्राई के पास पहुंचे। मोटे तौर पर अभी तक देश में इंटरनेट का मौजूदा सिस्टम उपभोक्ता हितों के अनुरूप ही रहा है।